पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 5501

==

देव नारायण साहू उर्फ देव नारायण साह, स्वर्गीय राम वृक्ष शाह के पुत्र, गाँव के निवासी- मेहसौल, वार्ड संख्या 7, डाकघर -मेहसौल, थाना -रुन्निसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत), सोन भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना राज्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से।
3. राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग (पंचायत), सोन भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना।
4. सचिव, राज्य चुनाव आयोग (पंचायत), सोन भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना।
5. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी।
6. निर्वाचन अधिकारी, पंचायत चुनाव, 2021, रुन्नीसैदपुर प्रखंड, जिला-सीतामढ़ी।
7. साजी अहमद, सफी अहमद के पुत्र, गाँव के निवासी और डाकघर मेहसौल, थाना रुन्निसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी।

.... उत्तरदातागण

==

रूपः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री एस. बी. के. मंगलम, अधिवक्ता

: श्री अवनीश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री कुमार आलोक (एससी 7)

एस. ई. सी. के लिए : श्री रवि रंजन, अधिवक्ता

==

रिट याचिका - चुनाव में अनियमितताओं का आरोप - *एक प्रतिवादी के मुखिया के रूप में चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की गई एवं चुनाव से जुड़े रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्यवाही पर आपत्ती जताई है।*

याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई पर प्रश्न उठाया है, जिन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की विशेषज्ञ टीम की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना और केवल एक इंजीनियर की सिफारिश के आधार पर संबंधित गांव के बूथ पर फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की।

निर्णय - मुंसिफ के समक्ष यह प्रमाण नहीं था कि मतपेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी, और ईवीएम की खराबी के वैज्ञानिक रिपोर्ट के बिना केवल इंजीनियर की सिफारिश पर कार्य करना पर्याप्त और व्यापक नहीं है। (पैरा 27)

कलेक्टर की यह टिप्पणी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है या यह गैर-कार्यात्मक है, मात्र संदेह पर आधारित है। ईवीएम की विशेषज्ञ वैज्ञानिक रिपोर्ट के अभाव में पुनर्मतदान के लिए पुनर्विचार करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है और इस पर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। वैकल्पिक उपाय का प्रतिबंध याचिकाकर्ता के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। हालांकि, विवादित प्रश्न को देखते हुए, ट्रिब्यूनल को सामग्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर विवाद का निपटारा कानून के अनुसार करना चाहिए। याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है। (पैरा 28)

भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) को निर्देश दिया जाता है कि वह ट्रिब्यूनल के समक्ष उस ईवीएम मशीन से संबंधित वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें चुनाव के वोट दर्ज किए गए हैं। (पैरा 29)

यदि राज्य निर्वाचन आयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की इंजीनियर टीम से ईवीएम मशीन से संबंधित विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत कराने में असमर्थ है, तो ऐसे मामले में, ट्रिब्यूनल को यह घोषणा करनी चाहिए कि अनुच्छेद 243(ओ) के प्रावधान का पालन न करने के कारण, जिला पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अनुसार, पुनः चुनाव नहीं कराया जाए। (पैरा 32)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति पुरनेन्दु सिंह

मौखिक निर्णय

तारीखः 29-01-2024

श्री एस. बी. के. मंगलम, श्री अवनीश कुमार के साथ, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुना; श्री कुमार आलोक राज्य के लिए विद्वान स्थायी सलाहकार 7 और श्री रवि रंजन, रा. नि. आ. के विद्वान वकील।

2. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों के लिए रिट याचिका दायर की हैः

(I) यह याचिका परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए और प्रत्यर्थी अधिकारियों को प्रत्यर्थी संख्या 7 सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज, गंगवाड़ा बुजर्ग के मुखिया के रूप में, इस आधार पर अमान्य करने के लिए दायर किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 7 के लिए प्रत्यर्थी सं 5 और 6 ने अपनी सभी सीमाएँ पार कर ली थीं जब उन्होंने मतों की गिनती के बाद ग्राम पंचायत राज, गंगवाड़ा बुजर्ग के बूथ संख्या 213 में 12.12.2021 को फिर से मतदान एक अलग पीठासीन अधिकारी द्वारा कराया और उक्त बूथ के पुनः मतदान के आधार पर, फिर से गिनती की गई थी और उक्त पुनः गिनती में, प्रतिवादी संख्या 7 को विजयी घोषित किया गया जबकि उक्त ग्राम पंचायत के सभी 13 बूथों पर हुए मतदान में याचिकाकर्ता 25 मतों के अंतर से चुनाव जीत रहा था।

(II) परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट जरी करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 को प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के विरूद्ध कठोर दंड की मांग की जाती है, क्योंकि उन्होंने उक्त ग्राम पंचायत के बूथ-संख्या 213 पर पुर्नमतदान कराकर तथा प्रतिवादी संख्या- 7 के उक्त ग्राम पंचायत के मुखिया पद से निएवाचित उम्मीदवार घोषित करके लोकतंत्र और ग्राम पंचायत राज, गंगवार बुजुर्ग मे रहने वाले मतदातओं के साथ धोखाधड़ी की है, अन्यथा बिहार राज्य में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा ।

(III) एक घोषणा के लिए कि हालांकि राज्य चुनाव आयोग का गठन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के गठन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, लेकिन यह कम से कम याचिकाकर्ता की ग्राम पंचायत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पंचायत चुनाव, 2021 आयोजित करने में बुरी तरह विफल रहा है, जबकि यह एक मूक दर्शक बना रहा है। राज्य चुनाव आयोग को प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के द्वारा किये गए जालसाजी की याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत सुचना दिया गया था।

(IV) किसी भी अन्य उपयुक्त रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करने के लिए जिसके लिए रिट याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत हकदार पाया जाएगा। "

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत राज गंगवाड़ा बुजर्ग के मुखिया पद के लिए 12.12.2021 को आयोजित मतदान में एक निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था, याचिकाकर्ता के पक्ष में कुल मतों की सबसे बड़ी संख्या सभी 13 बूथों में 1073 है, जैसा कि

अनुलग्नक पी1 से दिखाई देगा, जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 सहित किसी भी भाग लेने वाले उम्मीदवार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी। प्रतिवादी संख्या-7, कुल मिलाकर 1048 मत डाले गए और रिट याचिका के पैराग्राफ 9 में इस संबंध में एक विशिष्ट बयान दिया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता समर्पित किया कि किसी भी आपत्ति के अभाव में यह आरोप लगाते हुए कि ई. वी. एम. मशीन 2022 ठीक से नहीं गलत ढ़ंग से काम कर रही है, उन उम्मीदवारों से लेकर कार्य पर तैनात कार्यालय तक जो 12/12/2021 को वोट डालने या उसकी गिनती के समय मौजूद थे, प्रतिवादी संख्या-6, जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनका बूथ संख्या 213 पर 15/12/2021 को पुनर्मतदान करने का निर्देश देना अवैधानिक है तथा प्रतिवादी संख्या-7 के पक्ष में पक्षपातपूर्ण है, जिसने याचिकाकर्ता से कम मत प्राप्त किए थे । बूथ संख्या- 213 पर दिनांक 15/12/2021 को पुनर्मतदान के आधार पर प्रतिवादी संख्या-7 को 62 मतों के अंतर से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया गया है, जो कि प्रतिवादी संख्या-7 उक्त दिनांक 12/12/2021 को पुनर्मतगणना के लिए दायर किसी भी आपति के अभाव में अवैधानिक कारर्वाई है । विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने राज्य चुनाव आयोग गंगवारा बुजुर्ग, ग्राम पंचायत सीतामढ़ी के समक्ष दिनांक 18/12/2021 को अपनी शिकायत में प्रतिवादी संख्या-7 के पक्ष में संबंध्ति प्रतिवादियों के पक्षपातपूर्ण कार्रवाइयों के संबंध में विशिष्ट आपति उठाई है ।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी-सह-प्रखंड विकास अधिकारी, रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के अंतर्गत गंगवाड़ा बुजर्ग में बूथ संख्या 213 के लिए मतदान के दौरान बीईएल इंजीनियर द्वारा सीयू (एच 63448) में एक तकनीकी खराबी की सूचना दी गई थी, और इसलिए, निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत)-सह-खंड विकास अधिकारी, रुन्नीसैदपुर, जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत-सह-जिला मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी सीतामढ़ी की अनुशंसा फॉर्म 'ख' में उचित समीक्षा के बाद दिनांकित 14.12.2021

पत्र द्वारा, बूथ संख्या 213 के लिए पुनः मतदान की अनुशंसा की गई और इसे सचिव, राज्य चुनाव आयोग, बिहार, पटना को भेज दिया गया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ई. वी. एम. मशीन की खराबी के कारण 12.12.2021 को हुई गिनती का लाभ नहीं ले सकता है। बूथ संख्या 213 दिनांकित 15/12/2021 (अनुलग्नक पी/3) की पुनः गिनती के परिणाम-पत्रक से पता चलता है कि याचिकाकर्ता, देव नारायण साहू उर्फ देव नारायण साह को 190 वोट मिले, जबकि प्रतिवादी संख्या 7, यानी, साजी अहमद को 77 मिले। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मतदान की तारीख 12.12.2021 को, अर्थात्, ई. वी. एम. मशीन के आधार पर बूथ संख्या 233 की पुनः गिनती से पहले, याचिकाकर्ता को कुल 218 वोट मिले थे और प्रतिवादी संख्या 7 उन्हें केवल 18 वोट मिले थे। इन आधारों पर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने समर्पित किया कि कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि चुनाव से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, समाधान चुनाव याचिका दायर करके चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष निहित है और इस तरह रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।

6. राज्य चुनाव आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। हालाँकि, राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री रवि रंजन ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्य चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है और उन्होंने समर्पित किया कि याचिकाकर्ता के पास चुनाव याचिका दायर करके चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय है।

7. विद्वान वकील स्वीकार करते हैं कि ई. वी. एम. मशीन के काम न करने के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ रिपोर्ट के संबंध में कोई बयान नहीं है जिसमें 15.12.2021 को बूथ संख्या 213 पर फिर से मतदान करने और अन्य ई. वी. एम. मशीन के आधार पर गिनती करने की बात कही गई है।

8. पक्षों की ओर से किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद, स्वीकार किया गया तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 7 ई. वी. एम. मशीन के काम न करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है, और प्रखंड विकास अधिकारी-सह-निर्वाचन अधिकारी ने बी. ई. एल. के इंजीनियर की एक रिपोर्ट पर सी. यू. (एच. 63448) में ई. वी. एम. मशीन में तकनीकी खराबी होने का स्वतः अनुमान लगाया है। बी. ई. एल. की रिपोर्ट अभिलेख में नहीं लाई गई है। ई. वी. एम. मशीन में खराबी के संबंध में इंजीनियर की बी. ई. एल. रिपोर्ट की किसी भी रिपोर्ट के बिना, जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत)-सह-जिला दंडाधिकारी ने सचिव, राज्य चुनाव आयोग को बूथ संख्या 213 के पुनः मतदान के लिए सूचित किया।

9. प्रतिद्वंद्वी दलों के निवेदन और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्रियों को सुनने के बाद, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के संबंध में यह प्रश्न कि क्या, जवाबी हलफनामे में दिए गए केवल बयान पर कि जिला चुनाव अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया है और जिला दंडाधिकारी की सिफारिश पर राज्य चुनाव आयोग ने 12.12.2021 को हुए चुनाव को रद्द करने और 15.12.2021 को फिर से मतदान की तारीख की घोषणा करने में पूरी निष्पक्षता से काम किया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 7 को वापस उम्मीदवार घोषित किया गया था तथ्यों और परिस्थितियों में कि ई.वी.एम. मशीनों में 12.12.2021 को वोट डालने वाले वोटों को खराब किया गया था और किस आधार पर याचिकाकर्ता को वापस किया गया उम्मीदवार घोषित किया गया था और 15.12.2021 को हुए मतदान के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 7 उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया।

10. तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, चुनाव मामले में अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति को निष्पादित करने में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में कानून अब एकीकृत नहीं है। चुनाव के मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जो अब मुद्दे में नहीं है।

11. उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अभिलेख पर सामग्री को तर्कहीनता और विकृति के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी भी अवैधता को निर्धारित करने के लिए विचार कर सकता है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत के चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार (2000) 8 एस. सी. सी. 216** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया हैः -

"18. क्या संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा उच्च न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और अनुच्छेद 329 द्वारा बनाए गए प्रतिबंधों के बीच कोई टकराव है और यदि ऐसा है तो वे एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र [(1952) 1 एस.सी.सी. 94 : ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 64] में इस न्यायालय की संविधान पीठ के विचार के लिए कैसे सह-अस्तित्व में आएँगे। पोन्नुस्वामी [(1952) 1 एस. सी. सी. 94 में प्रतिपादित कानूनः ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 64] को मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामले में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा व्यापक रूप से निपटाया गया था, जिसे बढ़ाया भी गया था। [(1978) 1 एससीसी 405: ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 851] संविधान पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 329 की पूर्ण शक्ति दो सिद्धांतों पर आधारित हैः

(1) शीघ्रता की आकस्मिक तात्कालिकता कानूनी माध्यम से मध्यवर्ती व्यवधानों के बिना पूरी चुनाव प्रक्रिया की इंजीनियरिंग प्रारंभ और निष्कर्ष के बीच के चरणों और चरणों को चुनौती देने वाली कार्यवाहियां;

(2) एक विशेष क्षेत्राधिकार का प्रावधान जो चुनाव के अंत में एक पीड़ित पक्ष द्वारा लागू किया जा सकता है, अन्य रूप को शामिल नहीं करता है, अधिकार और उपचार कानूनों के प्राणी हैं और संविधान द्वारा नियंत्रित हैं।

इन सिद्धांतों पर *पोन्नुस्वामी मामले* [(1952) 1 एस. सी. सी. 94 ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 64] *मोहिंदर सिंह गिल मामले* [(1978) 1 एस. सी. सी. 405 ए. आई. आर 1978 एस. सी. 851]: (एस. सी. सी. पी. 426, पैरा 26) में निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार कटा गया था :-

"(1) लोकतांत्रिक देशों में विधायिकाओं द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए, यह हमेशा से रहा है प्रथम महत्व का विषय माना जाता है कि समय-सारणी के अनुसार जल्द से जल्द *चुनाव संपन्न किए जाने चाहिए और सभी चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादास्पद मामलों और सभी विवादों को चुनाव के बाद तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए। चुनाव समाप्त हो गए हैं, ताकि चुनाव की कार्यवाही अनावश्यक रूप से मंद या लंबी न हो।*

(2) इस सिद्धांत के अनुरूप, इस देश में चुनाव कानून की योजना जैसा कि इंग्लैंड में है कि किसी भी ऐसी चीज का कोई महत्व नहीं होना चाहिए जो 'चुनाव' को प्रभावित न करे; और, यदि कोई अनियमितताएं हो, तब की जाती हैं जब यह प्रगति पर होती है और वे उस श्रेणी या वर्ग से संबंधित होती हैं, जिसके तहत कानून के तहत चुनाव होते हैं। शासित हैं, *'चुनाव' को दूषित करने का प्रभाव होगा और प्रभावित व्यक्ति को इसे प्रश्न में बुलाने में सक्षम बनाएगा,* उन्हें होना चाहिए चुनाव याचिका के माध्यम से एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाता है और किसी भी अदालत के समक्ष विवाद का विषय नहीं बनाया जाता है, जबकि चुनाव चल रहा है। "

19. हालांकि, संविधान पीठ में *मोहिंदर सिंह गिल मामला* (1978) 1 एस. सी. सी. 405: ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 851] विरोध नहीं कर सका *पोन्नुस्वामी मामले* पर टिप्पणी करना [(1952) 1 एससीसी

94: ए. आई. आर. 1952 एस. सी.64] यह अवलोकन करते हुए (पैरा 25 के माध्यम से) कि अनुच्छेद 329 में अबाधित खंड अनुच्छेद 226 को बाहर कर देता है, जहां विवाद एक चुनाव पर सवाल उठाने का रूप लेता है, सिवाय उन विशेष स्थितियों के जिनमें इंगित किया गया है, लेकिन पोन्नुस्वामी मामले [(1952) 1 एस. सी. सी. 94', ए.आई.आर. 1952 एस. सी. 64 में छोड़ दिया गया हैः .

24. *दिग्विजय मोटे बनाम भारत संघ* [(1993) 4 एस. सी. सी. 175] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्तियां बेलगाम नहीं हैं; न्यायिक समीक्षा वैधानिक निकाय पर अनुमत होगी, अर्थात, चुनाव आयोग सार्वजनिक कानून अधिकारों को प्रभावित करने वाले अपने कार्यों का प्रयोग करेगा, हालांकि समीक्षा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी; अनुच्छेद 324 द्वारा चुनाव आयोग को प्रदान की गई शक्ति का उपयोग बिना सोचे-समझे, न दुर्भावनापूर्ण रूप से, न ही मनमाने ढंग से, न ही पक्षपात के साथ किया जाना चाहिए, बल्कि कानून के शासन के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रपति की अधिसूचना और न ही मौजूदा कानून को बाधित नहीं करना चाहिए।

32. सुविधा के लिए अब हम आम तौर पर अपने निष्कर्षों को दो संविधान पीठों द्वारा पहले ही कही गई बातों को आंशिक रूप से दोहराते हुए और फिर ऊपर किए गए हमारे विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट करते हुए जोड़ते हैंः

(1) यदि एक चुनाव, (चुनाव शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की जा रही है ताकि चुनाव की अधिसूचना की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा की तारीख तक सभी कदमों और पूरी कार्यवाही को

शामिल किया जा सके। प्रश्न में बुलाया जाना है और किस पूछताछ का चुनाव को बाधित करने या आगे बढ़ाने का प्रभाव हो सकता है किसी भी तरह से न्यायिक उपचार के आह्वान को चुनाव में कार्यवाही पूरी होने तक स्थगित करना पड़ता है।

(2) माँगा गया और दिया गया कोई भी निर्णय "चुनाव पर सवाल उठाने" के बराबर नहीं होगा यदि यह चुनाव की प्रगति को कम करता है और चुनाव को पूरा करने में मदद करता है। कुछ भी पूरा करने या करने की दिशा में किया गया चुनाव की कार्यवाही को आगे बढ़ाने को चुनाव पर सवाल उठाने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के अधीन, चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किए गए आदेश अच्छी तरह से तय किए गए मापदंडों पर न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं जो वैधानिक निकायों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा को सक्षम बनाते हैं जैसे कि दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है या वैधानिक निकाय ने कानून के उल्लंघन में काम किया है।

(4) चुनाव की कार्यवाही की प्रगति को बाधित, बाधित या विलंबित किए बिना, न्यायिक हस्तक्षेप उपलब्ध है यदि अदालत की सहायता केवल सुधार या सुधार के लिए मांगी गई है।चुनाव की प्रगति को सुगम बनाएँ कार्यवाही, उसमें बाधाओं को दूर करने के लिए, या सबूत के एक महत्वपूर्ण टुकड़े को संरक्षित करने के लिए यदि वह खो जाएगा या नष्ट हो जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा जब तक परिणाम घोषित किए जाते हैं और अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए चरण निर्धारित किया जाता है, तब तक इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।

(5) न्यायालय को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी चुनाव विवाद पर विचार करते समय सावधानी से कार्य करनाचाहिए, हालांकि यह अनुच्छेद 329 (बी) के प्रतिबंध से प्रभावित नहीं है, लेकिन चुनाव कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इसे लाया गया है। अदालत को चुनाव की कार्यवाही को रोकने, बाधित करने, रोकने या रोकने के किसी भी प्रयास से बचना चाहिए। यह देखने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक याचिका दायर करके अदालत के अनुग्रह का उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है जो बाहरी रूप से हानिरहित है, लेकिन अनिवार्य रूप से एक गुप्त या गुप्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक छल या बहाना है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चीजों की प्रकृति में अदालत अनिच्छा के साथ कार्य करेगी और कार्रवाई नहीं करेगी, सिवाय एक स्पष्ट और मजबूत मामले के कि उसके हस्तक्षेप के लिए विवरण और सटीकता के साथ याचिकाओं को उठाकर और आवश्यक सामग्री द्वारा इसका समर्थन करके किया गया है। ”

(जोर दिया गया)

12. चुनाव याचिका में कार्रवाई के कारण के रूप में भौतिक तथ्यों पर **(2009) 9 एस. सी. सी. 310 (अनिल वासुदेव सलगांवकर बनाम नरेश कुशाली शिगांवकर)** में विचार किया गया है, जो उस प्रकार हैः-

“57. यह तय कानूनी स्थिति है कि सीमा की अवधि के भीतर पक्ष द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में सभी "भौतिक तथ्यों" का अनुरोध किया जाना चाहिए। चूँकि इसका लक्ष्य और उद्देश्य विरोधी पक्ष को उस मामले को जानने में सक्षम बनाना है जिससे उसे मिलना है, इसलिए अभिवचन के अभाव में, किसी पक्ष को साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक भी भौतिक तथ्य बताने में विफल रहने पर चुनाव याचिका को

खारिज कर दिया जाएगा। चुनाव याचिका में "भौतिक तथ्यों" का एक संक्षिप्त बयान होना चाहिए जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। "

13. वर्तमान रिट याचिका के उचित निर्णय के लिए बिहार पंचायत अधिनियम, 2006 के प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक हैः --

"138. चुनाव में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक विषय हैं। - इस अधिनियम में कुछ भी निहित नहीं है -

(ए) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के के तहत बनाई गई या बनाई जानी चाहिए, पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा;

(बी) इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा किसी भी पंचायत के लिए किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

14. बिहार पंचायत चुनाव नियम, 2006 के नियम 72,73,74,76 और 79 को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

72. मतों की गिनती के स्थान का चयन। - मतों की गिनती के लिए स्थान का आयोग के निर्देशों के तहत जिला चुनाव अधिकारी द्वारा बनाया जाएगा।

73. मतों की गिनती का पर्यवेक्षण। - मतों की गिनती आयोग के निर्देश, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में की जाएगी।

" 74. गिनती के लिए निर्धारित स्थान पर प्रवेश करें। *- (1) निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी गणना स्थल से अन्य सभी व्यक्तियों को हटा देगा सिवाय इसके कि -*

(ए) ऐसे व्यक्ति जिन्हें वह गिनती में सहायता के लिए नियुक्त करता है;

(बी) आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति;

(सी) चुनाव के संबंध में कर्तव्य पर तैनात लोक सेवक; और

(डी) उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता।

(2) गिनती की मेज पर मतपेटिका खोलने से पहले, वहां मौजूद गणना एजेंटों को मतपेटियों और उनकी मुहरों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे संतुष्ट हो सकें कि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है।

(3) यदि निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि मतपेटी के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो वह उस मतपेटी के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा -

(ए) उस मतपेटी में निहित मतपत्रों की गिनती नहीं की जाएगी।

(बी) उपरोक्त खंड (ए) के संबंध में एक रिपोर्ट तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को भेजी जाएगी।

(4) उप-नियम 3 (बी) के तहत जानकारी प्राप्त करने और भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक निर्देश देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। ”

*“ **79. मतों की पुनः गणना। -** उम्मीदवार ने या उसकी अनुपस्थिति में उसका चुनाव अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को मतों की पुनः गिनती के लिए लिखित आवेदन कर सकता है जिसमें इसके लिए आधार बताए जा सकते हैं।*

(2) निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उसी के कारण बताते हुए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करें।

(3) यदि निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी उप-नियम (2) के तहत आवेदन को पूरी तरह या आंशिक रूप से स्वीकार करता है, तो वह मतपत्रों को पुनर्गणना कराएगा और नियम 76 के उप-नियम (2) में निर्धारित प्रपत्र में गिनती के परिणाम में संशोधन करेगा और परिणाम घोषित करेगा।

(4) उसके बाद पुनः गिनती के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। "

15. निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, जैसा कि नियम 76 के तहत परिकल्पना की गई है, जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रपत्र-19 में उम्मीदवार के अनुसार गिनती के परिणाम को दर्ज करना अनिवार्य करता है। नियम 76 को पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक हैः

" 76. मतों की गिनती। - (1) 'अस्वीकृत' मतों को छोड़कर, प्रत्येक मतपत्र की गिनती की जाएगी।

(2) मतों की गिनती पूरी होने पर निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी ग्राम सदस्य के मामले में प्रपत्र-19 में उम्मीदवार के अनुसार गिनती का परिणाम दर्ज करेंगे। ग्राम कछहरी की पंचायत/पंच और मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्य/जिला परिषद के सदस्य के मामले में प्रपत्र-20 में।

(3) इसके बाद, वैध मतों को एक अलग पैकेट में सील कर दिया जाएगा और

अस्वीकार किए गए मतों और उस पर दर्ज किए जाने वाले निम्नलिखित विवरणों के साथ एक साथ बंडल किया जाएगा। -

(ए) ग्राम पंचायत का नाम और ग्राम सदस्य के चुनाव के मामले में संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ग्राम कछहरी की पंचायत/पंच, ग्राम पंचायत का नाम और संख्या पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य के चुनाव के मामले में मुखिया/सरपंच का चुनाव और पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम और संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या,

(बी) मतदान केंद्र का नाम और क्रम संख्या जिससे मतपत्र संबंधित हैं; और

(सी) गणना की तिथि। "

16. अधिनियम, 2006 पर बारीकी से विचार करने पर भ्रष्ट आचरण की परिभाषा *धारा 141* में पाई जाती है और जिसमें *धारा 142* के तहत अयोग्यता शामिल है। नियम 106 में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की आवश्यकता है। नियम 108 के अनुसार चुनाव याचिका में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के तहत निर्धारित तरीके से याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित भौतिक तथ्यों और विवरणों का विवरण होगा। नियम 53 मतपत्रों के माध्यम से वोट डालने का प्रावधान करता है। नियम 54 में मतपेटिका का प्रावधान है। नियम 58 पीठासीन अधिकारी के लिए उन मतदाताओं की संख्या को विनियमित करने का प्रावधान करता है जो एक बार में मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं और अन्य व्यक्तियों को हटा सकते हैं। नियम 59 में मतदान शुरू होने से पहले मतपेटी को बंद करने और सील करने का प्रावधान है। *नियम 60* में पीठासीन अधिकारी को मतदाता की पहचान से संतुष्ट होने का प्रावधान है। मतदाता की पहचान को *नियम 61* के तहत चुनौती दी जा सकती है। बैलेट पेपर नियम 62 के तहत जारी किए जाते हैं। नियम 66 में मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटियों को सील करने का प्रावधान है। नियम 70 और 71 में मतदान की अवधि के दौरान और आपात स्थिति के मामले में मतदान को स्थगित करने का प्रावधान

है। नियम *74 (डी)* उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और गिनती एजेंट को गिनती के स्थान पर मौजूद रहने की अनुमति देता है। नियम 74 (2) में प्रावधान है कि मतपेटिका खोलने से पहले वहां उपस्थित गणना अभिकर्ता मतपेटियों और उनकी मुहरों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे संतुष्ट हो सकें कि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। नियम 75 मतपत्रों की जांच और उनकी अस्वीकृति का प्रावधान करता है। नियम 79 में उम्मीदवार/चुनाव एजेंट/गिनती एजेंट द्वारा निर्वाचन अधिकारी को दिए गए लिखित आवेदन पर मतों की फिर से गिनती का प्रावधान है। नियम 81 और 82 में परिणामों की घोषणा और चुनाव प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। नियम 97 में बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में मतों की गिनती का प्रावधान है।

17. बिहार पंचायत नियम, 2006 के नियम 111 के आधार पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को चुनाव याचिकाओं पर भी लागू किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अनुसार किसी मुकदमे या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो विफल हो जाएगा यदि दोनों तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया था। इसके अलावा, धारा 106 में यह प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है।

18. ***नन्हू मल और अन्य बनाम हीरा मल और अन्य, ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2140***, शीर्ष न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ***एन. पी. पुन्नूस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल और अन्य, ए.आई.आर. 1952 एससी 64*** के मामले में निर्धारित कानून पर भरोसा रखा जो वोट देने और चुनाव में खड़े होने का अधिकार को कानून का सृजन है । प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 5 को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"5. यह इस प्रकार है कि नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष के पद के लिए मतदान करने या चुनाव के लिए खड़े होने का अधिकार क़ानून, यानी

यू. पी. नगरपालिका अधिनियम का एक हिस्सा है और यह इसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन होना चाहिए। इसलिए, कार्यालय के लिए चुनाव राष्ट्रपति को केवल उस अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनौती दी जा सकती है और वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत एक चुनाव याचिका के माध्यम से है और किसी अन्य तरीके से नहीं। अधिनियम में केवल एक उपाय का प्रावधान है, वह उपाय एक चुनाव याचिका है जिसे चुनाव के बाद प्रस्तुत किया जाना है और किसी भी मध्यवर्ती चरण में कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है। ये निष्कर्ष इस मामले के तथ्यों पर अपने आवेदन में पोन्नुस्वामी के मामले (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 64) (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले का अनुसरण करते हैं। लेकिन ऊपर बताए गए निष्कर्ष अनुच्छेद 329 के प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना लिए गए थे। अनुच्छेद 329 के प्रावधान केवल इस हद तक प्रासंगिक हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार भी प्रावधानों के परिणामस्वरूप वर्जित है। लेकिन एक बार जब कानून के प्रावधान के ऊपर दिए गए कानूनी प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है, जिससे हम संबंधित हैं, तो उच्च न्यायालयों के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति हो सकती है जिसमें उच्च न्यायालय चुनावों के संबंध में अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अब इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। "

19. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों के क्रम में न्यायालयों को ऐसी तुच्छ चुनाव याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से आगाह किया है जो कार्रवाई करने के लिए भौतिक आधारों

का खुलासा करने में विफल रहती हैं और निश्चित रूप से मतपत्रों के निरीक्षण और पुनः गिनती के लिए आदेश पारित करने से बचती हैं।

20. **सुरेश प्रसाद यादव बनाम जय प्रकाश मिश्रा [(1975) 4 एस. सी. सी. 822]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मतपत्रों की पुनः गिनती निश्चित रूप से विषय नहीं हो सकती है और इसमें हस्तक्षेप के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैंः -

"इन दलीलों पर विचार करने से पहले, हम याद कर सकते हैं कि इस न्यायालय ने बार-बार क्या कहा है कि मतपत्रों के निरीक्षण और पुनः गिनती का आदेश निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता है। इसका कारण दो गुना है। सबसे पहले इस तरह का आदेश मतपत्र की गोपनीयता को प्रभावित करता है जिसे कानून के तहत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा, नियम मतपत्रों की गिनती के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में इतनी सारी वैधानिक जाँच और छल, गलतियों और गिनती में धोखाधड़ी के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय शामिल हैं, कि इसे लगभग मूर्खतापूर्ण कहा जा सकता है। यद्यपि कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी इस न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट व्यापक दिशानिर्देशों का संकेत इस प्रकार दिया जा सकता हैः

न्यायालय को मतपत्रों की पुनः गिनती का आदेश देना उचित होगा, केवल जहांः

(1) चुनाव याचिका में उन सभी भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण है जिन पर गिनती में अनियमितता या अवैधता के आरोप लगाए गए हैं।

(2) प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ऐसे आरोप प्रथम दृष्टया स्थापित होते हैं, जो यह विश्वास करने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करते हैं कि गिनती में गलती हुई है; और

(3) याचिका पर सुनवाई करने वाला न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि विवाद का फैसला करने और पक्षों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्याय करने के लिए इस तरह का आदेश देना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। "

इन सिद्धांतों को चंदा सिंह बनाम अध्याय शिव राम वर्मा [(1975) 4 एस. सी. सी. 393] में दोहराया गया था, जहां इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस प्रकार टिप्पणी कीः (एस. सी. सी. पृष्ठ 399, कंडिका 8)

"सभी तरफ, अब यह सहमति है कि मतपत्र की गोपनीयता के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, निरीक्षण के लिए प्रार्थना का समर्थन करने वाले भौतिक तथ्य प्रामाणिक, स्पष्ट और ठोस होने चाहिए और अच्छे साक्ष्य द्वारा समर्थित होने चाहिए। हम केवल इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि पूरी प्रक्रिया में, गोपनीयता पवित्र और अलंघनीय है, सिवाय इसके कि जहां गणना में शुद्धता, औचित्य और वैधता पर संदेह करने के लिए मजबूत प्रथम दृष्टया परिस्थितियों को निश्चित तथ्यात्मक कथनों विश्वसनीय प्रमाणिक प्रार्थना मे ही भोतिक और सद्भावना द्वारा बनाई गई हो । हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी जीतने वाले उम्मीदवार को फिर से गिनती से डरना नहीं चाहिए और अप्रत्याशित होने की उम्मीद करने वाला संदेहपूर्ण रवैया सही हो सकता है, जो निश्चित रूप से पहले से निर्धारित व्यापक कानूनी दिशानिर्देशों द्वारा सूचित किया गया है। "

21. **ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल (1982) 1 एस. सी. सी. 691** मामले में सर्वोच्च न्यायालय, ने अभिनिर्धारित किया है कि एक चुनाव याचिका सांविधिक कार्यवाही है जो उन नियमों द्वारा विनियमित होती है जो क़ानून बनाता है और लागू होता है, इसलिए, एक निर्वाचित प्रतिनिधि के चुनाव को केवल प्रासंगिक प्रतिमा में प्रदान किए गए तरीके से चुनौती दी जानी चाहिए। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

> *"चुनने का अधिकार, हालांकि यह लोकतंत्र के लिए मौलिक है, विसंगत रूप से न तो एक मौलिक अधिकार है और न ही एक सामान्य कानून अधिकार है। यह विशुद्ध और सरल, एक वैधानिक अधिकार है। निर्वाचित होने का अधिकार भी है। चुनाव पर विवाद करने का भी यही अधिकार है। कानून के बाहर, चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं है, निर्वाचित होने का कोई अधिकार नहीं है, और चुनाव पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है। सांविधिक सृजन वे हैं, और इसलिए, सांविधिक सीमा के अधीन हैं। चुनाव याचिका सामान्य कानून पर कार्रवाई नहीं है, न ही निष्पक्षता में। यह एक सांविधिक कार्यवाही है जिसमें न तो सामान्य कानून और न ही समता के सिद्धांत लागू होते हैं, बल्कि केवल वे नियम लागू होते हैं जिन्हें क़ानून बनाता है और लागू करता है। यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र है, और एक विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हमेशा इसे बनाने वाले क़ानून के अनुसार किया जाना चाहिए। सामान्य कानून और समानता से परिचित अवधारणाओं को तब तक चुनाव कानून के लिए अजनबी रहना चाहिए जब तक कि वैधानिक रूप से मूर्त न हो। एक अदालत को कथित नीति के विचारों पर उनका सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में नीति, जैसे - चुनाव विवादों के मुकदमे से संबंधित,*

वही है जो क़ानून निर्धारित करता है। चुनाव विवादों के मुकदमे में, अदालत को एक जलडमरूमध्य में रखा जाता है। ....”

22. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ जहाँ तक चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक का संबंध है, भारत का संविधान अनुच्छेद 329 (बी) के समान है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ (बी) में निहित बाधा और जैसा कि ऊपर कहा गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई कानून की स्थिति को देखते हुए, 2006 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी चुनाव की वैधता पर 2006 के अधिनियम की धारा 137 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव याचिका के माध्यम से ही सवाल उठाया जा सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 243-ओ (बी) किसी भी पंचायत के चुनाव के मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है, सिवाय उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के माध्यम से और उस तरीके से जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया है। इस प्रावधान के आलोक में, एक अंतर बनाए जाने की आवश्यकता है *"ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई एक चुनाव याचिका के बीच और इस तरह से जो किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया है।* किसी राज्य के विधान-मंडल और अन्य आनुषंगिक मामले जिनके लिए राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाए गए सुसंगत अधिनियमों और नियमों में प्रावधान नहीं किया गया है। रोक विशेष रूप से पहले वाले के संबंध में है लेकिन बाद वाले को अदालतों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप से वर्जित के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए जहां असाधारण परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तो वैकल्पिक उपाय को बाहर निकाला जा सकता है।

23. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने प्रखंड विकास अधिकारी-सह-वापसी अधिकारी के साथ-साथ जिला चुनाव अधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी की कार्रवाई पर सवाल

उठाया है, जिन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के विशेषज्ञ दल द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना और केवल एक इंजीनियर की सिफारिश के आधार पर संबंधित गांव के बूथ संख्या 213 पर नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश की है। इस न्यायालय ने जिला दंडाधिकारी की कार्रवाई को सही करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, जिन्होंने दुर्भावनापूर्ण और अधिकार क्षेत्र के बिना और केवल एक इंजीनियर की सिफारिश पर ई. वी. एम. मशीन के काम करने के संबंध में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की विशेषज्ञ रिपोर्ट प्राप्त किए बिना मशीन का मूल्यांकन करने के लिए फिर से मतदान करने की घोषणा की है, मशीन को दोषपूर्ण पाया है।

24. हाल ही में, ***सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वपल्ली रमैया बनाम जिला कलेक्टर, चितूर, (2019) 4 एस. सी. सी. 500*** के मामले में निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः -

> **"40.** प्रशासनिक निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, केवल विकृति, पेटेंट अवैधता, तर्कहीनता, निर्णय लेने की शक्ति की कमी और प्रक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर इन आधारों को छोड़कर, न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति के प्रयोग में प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।
>
> **43.** अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा निर्णय के खिलाफ नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के खिलाफ निर्देशित है। बेशक, निर्णय के सामने एक पेटेंट अवैधता और/या स्पष्ट त्रुटि, जो निर्णय की जड़ तक जाती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को दूषित कर सकती है।

25. चुनाव याचिका में आवश्यक "भौतिक तथ्य" **(2009) 9 एस. सी. सी. 310 (अनिल वासुदेव सलगांवकर बनाम नरेश कुशाली शिगांवकर)** में निम्नलिखित रूप में माना गया है।:

> "57. यह तय कानूनी स्थिति है कि सीमा की अवधि के भीतर पक्ष द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में सभी "भौतिक तथ्यों" का अनुरोध किया जाना चाहिए। चूँकि इसका उद्देश्य और उद्देश्य विरोधी पक्ष को उस मामले को जानने में सक्षम बनाना है जिससे उसे मिलना है, इसलिए अभिवचन के अभाव में, किसी पक्ष को साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक भी भौतिक तथ्य बताने में विफल रहने पर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। चुनाव याचिका में "भौतिक तथ्यों" का एक संक्षिप्त बयान होना चाहिए जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। "

26. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.12.2021 (अनुलग्नक 4) को आपत्ति दायर की है, इस मामले की जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की विशेषज्ञ वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर की जानी चाहिए, कि क्या, बूथ संख्या 213 पर मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों वाली ई. वी. एम. मशीन, जिस पर याचिकाकर्ता को वापस आया उम्मीदवार घोषित किया गया था, की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा वैज्ञानिक रूप से जांच की जानी चाहिए और यह रिपोर्ट देनी चाहिए कि वह काम नहीं कर रही थी और रिपोर्ट समर्पित की जाती है । प्रतिवादी संख्या-7 द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर इस न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी और इसलिए जिला दंडाधिकारी द्वारा पाया गया।

27. मुन्सिफ के समक्ष इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मतपेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी और ई. वी. एम. की खराबी की वैज्ञानिक रिपोर्ट के बिना इंजीनियर की सिफारिश पर कार्रवाई करना निराधार और व्यापक है।

28. कलेक्टर की यह टिप्पणी कि ई. वी. एम. को या तो कम किया गया है या काम नहीं कर रहा है, केवल एक संदेह है और पुनः मतदान के लिए पुनर्विचार करना **सुरेश प्रसाद यादव (उपरोक्त)** मामले में शीर्ष अदालत के निर्देश की अवहेलना है और

अनिल वासुदेव सलगांवकर बनाम नरेश कुशाली शिगांवकर (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है, और विशेषज्ञ वैज्ञानिक रिपोर्ट के अभाव में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है जो उसके सामने उपलब्ध नहीं थी या याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं की गई थी। वैकल्पिक उपचार का प्रतिबंध याचिकाकर्ता के लिए एक तरह से बाधा नहीं होगा। हालाँकि, विवादित प्रश्न पर विचार करते हुए, न्यायाधिकरण को सामग्री के आधार पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष दिनांक 18.12.2021 को दायर आपत्ति और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार विवाद का फैसला करना शामिल है। याचिकाकर्ता को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता है।

29. बी. ई. एल. को ई. वी. एम. मशीन से संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जिसने इस आदेश के संचार की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर बूथ संख्या 213 के संबंध में 12.12.2021 को हुए चुनाव के मत दर्ज किए हैं।

30. जिला दंडाधिकारी की कार्रवाई शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, क्योंकि बूथ पर नए सिरे से चुनाव कराने और आयोजित करने की सिफारिश तब तक की जा सकती है जब तक कि ई. वी. एम. मशीनों की कथित खराबी के बारे में विशेषज्ञ रिपोर्ट द्वारा दोषों की पुष्टि नहीं की जाती है।

31. याचिकाकर्ता और वापस लौटे उम्मीदवार को एक सप्ताह के भीतर चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होना चाहिए। राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादी सं. 7, घोषित वापसी वाला उम्मीदवार कौन है।

32. न्यायाधिकरण को आगे निर्देश दिया जाता है कि यदि राज्य चुनाव आयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इंजीनियर की टीम से ई. वी. एम. मशीन से संबंधित विशेषज्ञ रिपोर्ट लाने की स्थिति में नहीं है, तो उस मामले में न्यायाधिकरण को बाद के

चुनाव की घोषणा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो बूथ संख्या 213 के संबंध में 15.12.2021 को आयोजित किया गया था। जिला पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित नहीं किया जाएगा, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ओ) के जनादेश का पालन नहीं किया है। किसी भी मामले में उपरोक्त अभ्यास न्यायाधिकरण द्वारा इस आदेश के पारित होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए।

33. चूंकि राज्य प्राधिकारी की निष्पक्षता के संबंध में सवाल उठाया गया है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इंजीनियर की विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट को इस आदेश के संचार की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य है, ताकि किसी भी स्तर पर आगे कोई हेरफेर न किया जा सके।

34. काल बाधा का प्रश्न याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आएगा। न्यायाधिकरण को योग्यता के आधार पर चुनाव याचिका पर निर्णय लेने में राज्य अधिकारियों के साथ-साथ आयोग की निष्पक्षता का न्याय करना आवश्यक है।

35. रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(पूर्णेन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।